गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 064
दि. 03.07.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अब गांवों की हर सड़क की होगी डिजिटल पहचान, पेड़-पोखर नहीं बल्कि नाम, यूनिक कोड और क्यूआर सिस्टम से मिलेगा पता

नई दिल्ली। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी घर या गली का पता पूछने पर अक्सर जवाब मिलता है—"पीपल के पेड़ से बाएं मुड़ जाइए", "हैंडपंप के पास वाली गली है", "मंदिर के पीछे तीसरा मकान" या "चौपाल के सामने वाला घर"। वर्षों से गांवों में यही पारंपरिक पता प्रणाली चली आ रही है। स्थानीय लोगों के लिए यह व्यवस्था भले ही सहज हो, लेकिन बाहरी व्यक्ति, डाक कर्मचारी, एंबुलेंस चालक, पुलिस, अग्निशमन दल, ई-कॉमर्स कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के लिए सही स्थान तक पहुंचना अक्सर चुनौती बन जाता है। अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंचायतीराज मंत्रालय ने गांवों की अंदरूनी सड़कों को आधुनिक डिजिटल पहचान देने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत प्रत्येक सड़क को नाम, यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड, डिजीपिन (DigiPin) आधारित डिजिटल पहचान और क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण भारत को भी आधुनिक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम से जोड़ना है, ताकि गांवों में भी शहरों जैसी सटीक लोकेशन और नेविगेशन सुविधा उपलब्ध हो सके।

यह पहल 'होल ऑफ गवर्नमेंट' (Whole of Government) दृष्टिकोण के तहत तैयार की जा रही है, जिसमें पंचायतीराज मंत्रालय के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्रालय और विभाग भी सहयोग करेंगे। योजना का उद्देश्य केवल गांवों की सड़कों का नामकरण करना नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण सड़क नेटवर्क को एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान करना है। इसके तहत प्रत्येक सड़क का पूरा विवरण राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा और उसे ग्राम मानचित्र, डिजीपिन प्रणाली तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इससे देश के किसी भी हिस्से से उस सड़क की सटीक पहचान संभव होगी।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार वर्तमान समय में देश के अधिकांश गांवों की आंतरिक सड़कों का कोई मानकीकृत नाम या आधिकारिक कोड उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि जीपीएस आधारित नेविगेशन भी गांवों के भीतर कई बार सही दिशा नहीं बता पाता। डाक विभाग को पत्र और पार्सल पहुंचाने में अतिरिक्त समय लगता है, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवाओं को सही स्थान तक पहुंचने में कठिनाई होती है तथा ई-कॉमर्स कंपनियों को अंतिम छोर तक डिलीवरी करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नई प्रणाली लागू होने के बाद इन सभी सेवाओं की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

योजना के तहत प्रत्येक सड़क को एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक (अक्षर और अंक आधारित) यूनिक कोड दिया जाएगा। इसके साथ सड़क का आधिकारिक नाम भी निर्धारित किया जाएगा। यह जानकारी डिजीपिन प्रणाली और ग्राम मानचित्र से जुड़ी रहेगी, जिससे सड़क की भौगोलिक स्थिति, लंबाई, श्रेणी और प्रशासनिक विवरण एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इससे सरकारी विभागों के बीच डेटा साझा करना भी आसान होगा और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ आपातकालीन सेवाओं को मिलने वाला है। वर्तमान में कई बार दुर्घटना, बीमारी या आग लगने जैसी आपात स्थितियों में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को गांव के भीतर सही स्थान तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। स्थानीय लोगों से बार-बार रास्ता पूछना पड़ता है, जिससे बहुमूल्य समय नष्ट होता है। डिजिटल सड़क पहचान प्रणाली लागू होने के बाद संबंधित वाहन सीधे निर्धारित लोकेशन तक पहुंच सकेंगे। इससे आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होगी और समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

डाक विभाग और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी यह योजना अत्यंत उपयोगी मानी जा रही है। आज ऑनलाइन खरीदारी गांवों तक तेजी से पहुंच रही है, लेकिन स्पष्ट पते के अभाव में कई बार पार्सल समय पर नहीं पहुंच पाते। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू होने के बाद प्रत्येक सड़क की स्पष्ट पहचान होगी, जिससे अंतिम छोर तक सामान की डिलीवरी अधिक तेज, सटीक और विश्वसनीय हो सकेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी शहरों की तरह बेहतर डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से केवल नागरिक सुविधाओं में सुधार नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी। वर्तमान में कई गांवों में एक ही सड़क विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड में अलग-अलग नामों से दर्ज होती है या उसका कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता। इससे विकास कार्यों की निगरानी कठिन हो जाती है और कई बार एक ही सड़क पर अलग-अलग योजनाओं के तहत कार्य दिखाने या दोबारा स्वीकृति प्राप्त करने जैसी अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है। प्रत्येक सड़क को यूनिक कोड मिलने के बाद उसके निर्माण, मरम्मत, रखरखाव, स्वीकृत बजट और कार्य प्रगति की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। इससे सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

योजना के तहत प्रत्येक सड़क पर लगाए जाने वाले साइनबोर्ड में क्यूआर कोड भी शामिल किया जाएगा। कोई भी नागरिक या अधिकारी मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर संबंधित सड़क की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसमें सड़क का नाम, यूनिक कोड, स्थान, ग्राम पंचायत, संबंधित प्रशासनिक इकाई तथा अन्य तकनीकी विवरण उपलब्ध होंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों, सर्वेक्षण टीमों, इंजीनियरों और आम नागरिकों को समान रूप से सुविधा मिलेगी।

पंचायतीराज मंत्रालय ने प्रस्तावित रोड कोडिंग और ग्रेडिंग प्रणाली को डिजीपिन, ग्राम मानचित्र और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड कोडिफिकेशन मानकों से जोड़ने का प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत सड़कों का वर्गीकरण मुख्य सड़क, क्रॉस रोड और अन्य संपर्क मार्गों के रूप में किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग पहचान और प्रशासनिक कोड निर्धारित किए जाएंगे, जिससे पूरे ग्रामीण सड़क नेटवर्क का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार हो सके।

इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में स्वामित्व (SVAMITVA) योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों का डिजिटल सर्वेक्षण पहले से ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग छह लाख आबाद गांव हैं। इनमें से लगभग 3.38 लाख गांवों को स्वामित्व योजना के तहत अधिसूचित किया जा चुका है, जबकि लगभग 3.30 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अब इन्हीं डिजिटल मानचित्रों और सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर गांवों की आंतरिक सड़कों को भी डिजिटल पहचान प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का पराक्रम, समुद्री लुटेरों के कब्जे की कोशिश विफल, भारत आ रहे मालवाहक जहाज को सुरक्षित बचाया

बंगलूरू। अदन की खाड़ी में एक बार फिर भारतीय नौसेना ने अपनी त्वरित कार्रवाई और समुद्री सुरक्षा क्षमता का परिचय देते हुए भारत के लिए महत्वपूर्ण माल लेकर आ रहे एक व्यापारी जहाज को समुद्री लुटेरों के कब्जे में जाने से बचा लिया। संदिग्ध समुद्री डाकुओं ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी, लेकिन संकट संदेश मिलते ही भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड तत्काल मौके पर पहुंच गया। नौसेना की मौजूदगी देखते ही हमलावर घबरा गए और जहाज छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद भारतीय नौसेना के विशेष मरीन कमांडो मार्कोस (MARCOS) ने जहाज पर व्यापक तलाशी अभियान चलाकर उसे पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया। इस सफल अभियान ने एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा प्रतिबद्धता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को साबित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी गोल्डन आर्सेनल नाम का व्यापारी जहाज भारत के लिए महत्वपूर्ण माल लेकर अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर निर्धारित यात्रा कर रहा था और उसके चालक दल में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। इसी दौरान संदिग्ध समुद्री लुटेरों ने तेज गति वाली नौकाओं के माध्यम

से जहाज के करीब पहुंचकर उस पर चढ़ने का प्रयास किया। प्रारंभिक संकेत मिलते ही चालक दल ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तत्काल आपातकालीन व्यवस्था लागू कर दी।

खतरे को देखते हुए चालक दल के सभी सदस्य जहाज के सुरक्षित कक्ष (सिटाडेल) में चले गए, जहां से उन्होंने आपातकालीन संचार प्रणाली के माध्यम से भारतीय नौसेना सहित समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को संकट संदेश भेजा। संदेश मिलते ही क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा गश्त पर तैनात भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड को तत्काल जहाज की सहायता के लिए रवाना किया गया। नौसेना ने बिना समय गंवाए पूरी गति से घटनास्थल की ओर बढ़ते हुए व्यापारी जहाज तक पहुंचने का अभियान शुरू किया।

जैसे ही आईएनएस त्रिकंड संदिग्ध जहाज के निकट पहुंचा, समुद्री लुटेरों की गतिविधियों में अचानक बदलाव देखा गया। भारतीय युद्धपोत की मौजूदगी और संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका से घबराकर हमलावर जहाज को छोड़कर तेजी से वहां से फरार हो गए। इस प्रकार व्यापारी जहाज पर कब्जा करने की उनकी पूरी साजिश विफल हो गई।

हालात पूरी तरह सामान्य होने से पहले भारतीय नौसेना ने कोई जोखिम नहीं लिया। युद्धपोत से विशेष प्रशिक्षित मार्कोस कमांडो व्यापारी जहाज पर उतरे और पूरे पोत का विस्तृत सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया। कमांडो ने जहाज के प्रत्येक डेक, इंजन कक्ष, कंटेनर क्षेत्र, चालक दल के रहने के स्थान और अन्य सभी हिस्सों की गहन तलाशी ली, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या विस्फोटक सामग्री जहाज पर मौजूद न हो। विस्तृत जांच पूरी होने के बाद नौसेना ने जहाज को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया और चालक दल को आगे की यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी।

भारतीय नौसेना के अधिकारियों के अनुसार अदन की खाड़ी और उसके आसपास का समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में समुद्री डकैती की घटनाएं वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। यही कारण है कि भारतीय नौसेना लंबे समय से इस क्षेत्र में लगातार निगरानी, गश्त और सुरक्षा अभियान संचालित कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ने के बाद भारत ने अपने नौसैनिक अभियानों को और मजबूत किया है। भारतीय युद्धपोत नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निगरानी रखते हैं तथा संकट की स्थिति में व्यापारी जहाजों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराते हैं। नौसेना की इस सक्रिय रणनीति के कारण कई भारतीय और विदेशी व्यापारी जहाज संभावित हमलों से सुरक्षित बचाए जा चुके हैं।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय नौसेना की त्वरित प्रतिक्रिया केवल भारतीय जहाजों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री व्यापार को भी मजबूती मिलती है। भारत की बढ़ती आर्थिक भूमिका और वैश्विक व्यापार में बढ़ते योगदान को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

टीएमसी के बैंक खातों पर हाई कोर्ट की पैनी नजर बैंक से मांगा पूरा हिसाब, पुलिस रिकॉर्ड भी होंगे पेश

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बैंक खातों को लेकर चल रहे विवाद ने अब नया कानूनी मोड़ ले लिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित निजी बैंक को निर्देश दिया कि वह पार्टी के तीनों बैंक खातों में जमा राशि और उनसे जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन का विस्तृत विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही बिधाननगर पुलिस को भी शिकायत, एफआईआर और अब तक की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अगली सुनवाई में पेश करने की अनुमति दे दी गई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह इस मामले में वित्तीय पारदर्शिता और वैध अधिकारों के प्रश्न पर पूरी गंभीरता से विचार कर रहा है।

मामला टीएमसी के ममता बनर्जी गुट द्वारा दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें पार्टी के बैंक खातों पर लगाए गए डेबिट फ्रीज़ को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि खातों से धन निकासी पर रोक लगाए जाने से पार्टी की नियमित प्रशासनिक और संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। उनका दावा है कि बैंक खातों का संचालन रोकने की कार्रवाई उचित कानूनी आधार के बिना की गई है, जिससे राजनीतिक दल के वैध अधिकारों का हनन हो रहा है।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ में हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान संबंधित निजी बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 7 जुलाई तक टीएमसी के तीनों बैंक खातों में उपलब्ध राशि, हाल के लेन-देन, हस्ताक्षरकर्ताओं की स्थिति और अन्य वित्तीय विवरणों की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करें। अदालत ने कहा कि इन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद ही मामले के अगले चरण पर विचार किया जाएगा। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान बिधाननगर पुलिस की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि फिलहाल किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित न किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और उसके पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो सकता है कि बैंक खातों से धन के कथित गबन या अनुचित निकासी का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने अदालत से कुछ समय देने का अनुरोध किया ताकि जांच से संबंधित सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकें।

तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि खातों पर रोक क्यों लगाई गई, बल्कि यह है कि टीएमसी के दो गुटों में से बैंक खातों का संचालन करने का वैध अधिकार आखिर किसके पास है। उनके अनुसार जब तक इस प्रश्न का स्पष्ट कानूनी समाधान नहीं हो जाता, तब तक बैंक खातों के संचालन को लेकर सतर्कता बरतना आवश्यक है। हाई कोर्ट ने पुलिस को शिकायत, एफआईआर, जांच रिपोर्ट तथा अन्य सभी संबंधित रिकॉर्ड अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए कहा कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करेगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो वह सभी दस्तावेजों और जांच सामग्री का विस्तार से परीक्षण करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने एक महत्वपूर्ण संभावना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अदालत इस विकल्प पर विचार कर रही है कि जब तक याचिका का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक टीएमसी के इन तीनों बैंक खातों का संचालन अदालत द्वारा नियुक्त संयुक्त विशेष अधिकारियों की निगरानी में कराया जाए। अदालत ने कहा कि इन विशेष अधिकारियों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, जो खातों से होने वाले प्रत्येक वित्तीय लेन-देन की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। हालांकि इस संबंध में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, लेकिन अदालत की इस टिप्पणी से स्पष्ट संकेत मिला है कि वह मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए न्यायिक निगरानी का विकल्प भी खुला रखना चाहती है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले पर विशेष नजर बनी हुई है, क्योंकि यह केवल बैंक खातों के संचालन का विवाद नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दल के संगठनात्मक नियंत्रण, वित्तीय अधिकार और वैध प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा हुआ है। यदि अदालत न्यायिक निगरानी में खातों के संचालन का आदेश देती है, तो यह भविष्य में राजनीतिक दलों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। अब सभी की निगाहें 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन बैंक द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरण, पुलिस जांच के रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर हाई कोर्ट यह तय कर सकता है कि डेबिट फ्रीज़ जारी रहेगा, उसमें राहत दी जाएगी या फिर खातों के संचालन के लिए अदालत की निगरानी में कोई अंतरिम व्यवस्था लागू की जाएगी।

एआई की नई दौड़: 'जीएलएम 5.2' ने बढ़ाई रफ्तार, साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर भी बढ़ी चुनौती

नई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की वैश्विक प्रतिस्पर्धा अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। चीन की उभरती हुई स्टार्टअप कंपनी जे.एआई (J.AI) ने अपना अत्याधुनिक एआई मॉडल 'जीएलएम 5.2' (GLM 5.2) लॉन्च कर तकनीकी जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल केवल एक नया चैटबॉट नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के एजेंटिक एआई (Agentic AI) का उदाहरण है, जो स्वयं निर्णय लेने, जटिल कार्यों की योजना बनाने और उन्हें कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ पूरा करने में सक्षम है। इसकी क्षमताओं की तुलना दुनिया के अग्रणी एआई मॉडलों से की जा रही है, जिससे वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है।

जीएलएम 5.2 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी असाधारण प्रोसेसिंग क्षमता और विश्लेषणात्मक दक्षता है। जहां सामान्य एआई मॉडल उपयोगकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देने तक सीमित रहते हैं, वहीं यह मॉडल विशाल सॉफ्टवेयर कोडबेस, हजारों पन्नों के तकनीकी दस्तावेज, कानूनी फाइलें और जटिल डाटा सेट को कुछ ही सेकंड में पढ़कर उनका विश्लेषण करने में सक्षम बताया जा रहा है। इससे सॉफ्टवेयर विकास, अनुसंधान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वित्त और वैज्ञानिक परियोजनाओं में काम करने वाले पेशेवरों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। बड़ी कंपनियां इसे जटिल परियोजनाओं के प्रबंधन, कोड समीक्षा, त्रुटि पहचान और स्वचालित समाधान विकसित करने जैसे कार्यों में उपयोगी मान रही

हैं। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार यह मॉडल पारंपरिक एआई की तुलना में अधिक स्वायत्त तरीके से कार्य करता है। यदि इसे कोई जटिल लक्ष्य दिया जाए तो यह उसे छोटे-छोटे चरणों में विभाजित कर स्वयं कार्ययोजना तैयार कर सकता है, आवश्यक जानकारी जुटा सकता है और समाधान तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। यही कारण है कि इसे केवल एक भाषा मॉडल नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान डिजिटल सहायक के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में उद्योगों की कार्यशैली बदल सकता है।

जे.एआई ने इस मॉडल को डेवलपर समुदाय के लिए अपेक्षाकृत खुला रखने की रणनीति अपनाई है। इससे दुनिया भर के शोधकर्ता और सॉफ्टवेयर डेवलपर इसे डाउनलोड कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की ओपन डेवलपमेंट नीति नवाचार को गति दे सकती है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ जाते हैं।

यही कारण है कि जीएलएम 5.2 के लॉन्च के साथ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि इस तरह के शक्तिशाली मॉडल का उपयोग जिम्मेदारी से न किया जाए या इसके सुरक्षा नियंत्रणों को हटाकर गलत हाथों में पहुंचा दिया जाए, तो यह साइबर अपराधियों के लिए अत्यंत प्रभावशाली हथियार साबित हो सकता है। यह मॉडल किसी सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को अत्यधिक तेजी से पहचान सकता है। यदि हैकर इसका दुरुपयोग करें तो वे बड़ी संख्या में साइबर हमलों की योजना बनाने, सुरक्षा खामियों का फायदा उठाने और जटिल डिजिटल नेटवर्क को निशाना बनाने में सक्षम हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में साइबर सुरक्षा की लड़ाई केवल इंसानों और हैकरों के बीच नहीं रहेगी, बल्कि एआई बनाम एआई की हो जाएगी। एक ओर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हमले के लिए करेंगे तो दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी कंपनियों को भी एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियों के जरिए उन हमलों का मुकाबला करना होगा। इसलिए केवल एआई विकसित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सुरक्षित, जिम्मेदार और नियंत्रित एआई प्रणाली विकसित करना भी उतना ही आवश्यक होगा।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच एआई नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। एक ओर अमेरिकी कंपनियां अत्याधुनिक जनरेटिव एआई मॉडल विकसित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर चीन भी अपने घरेलू एआई इकोसिस्टम को तेजी से मजबूत कर रहा है। जीएलएम 5.2 का आगमन इसी प्रतिस्पर्धा का नया अध्याय माना जा रहा है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक रणनीति का प्रमुख आधार बनने वाली है।

भारतीय विशेषज्ञ इस घटनाक्रम को भारत के लिए चेतावनी के बजाय अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि भारत को केवल विदेशी एआई मॉडल अपनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने मजबूत और आत्मनिर्भर एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, निजी स्टार्टअप, उद्योग और सरकार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक होगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण और नियामक ढांचे को भी समान प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करना समय की मांग है। साथ ही घरेलू, व्यावसायिक और ओपन-सोर्स एआई प्रणालियों का संतुलित एवं सुरक्षित मिश्रण तैयार करना भी जरूरी होगा, ताकि तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकें। तकनीकी जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, रक्षा, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं सहित लगभग हर क्षेत्र में एआई की भूमिका और व्यापक होगी।

संपादकीय

तेजी, पारदर्शिता और भरोसे की ओर बढ़ता न्याय तंत्र

किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास, आधुनिक आधारभूत संरचना या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वहां की न्याय व्यवस्था कितनी प्रभावी, निष्पक्ष और आम नागरिक के लिए सुलभ है। यदि किसी व्यक्ति को अपराध का शिकार होने के बाद अपनी शिकायत दर्ज कराने में कठिनाई हो, जांच वर्षों तक अधूरी रहे, गवाहों को समय पर बुलावा न मिले और अदालतों में मुकदमे पीढ़ियों तक चलते रहें, तो कानून का भय कम होने लगता है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। भारत में लंबे समय तक आपराधिक न्याय प्रणाली ऐसी ही अनेक चुनौतियों का सामना करती रही। बदलते समय, बढ़ते अपराधों और डिजिटल युग की आवश्यकताओं को देखते हुए न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी सोच के साथ लागू किए गए नए आपराधिक कानून और उनसे जुड़े प्रशासनिक सुधार देश की न्याय प्रणाली को नई दिशा देने का प्रयास हैं।

वर्षों तक चली पुरानी व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या प्रक्रियाओं की जटिलता और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी थी। पुलिस, अभियोजन, फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, न्यायालय और जेल प्रशासन अपने-अपने स्तर पर कार्य करते थे, लेकिन उनके बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज और व्यवस्थित नहीं था। परिणामस्वरूप एक ही जानकारी कई बार दर्ज करनी पड़ती थी, दस्तावेजों के सत्यापन में समय लगता था और मामूली प्रशासनिक देरी भी मुकदमों को वर्षों तक लंबित रख देती थी। सबसे अधिक परेशानी पीड़ित और गवाहों को होती थी, जिन्हें बार-बार कार्यालयों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे न्याय मिलने की प्रक्रिया कठिन और थकाऊ बन जाती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल पुराने कानूनों को बदलना नहीं, बल्कि न्याय को अधिक मानवीय और उत्तरदायी बनाना है। अब ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि पीड़ित को न्याय प्रक्रिया का केंद्र बनाया जाए। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे जांच की प्रगति की जानकारी मिले, साक्ष्यों का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से संग्रह हो, जांच तय समय के भीतर पूरी हो तथा मुकदमे की सुनवाई अनावश्यक रूप से लंबी न खिंचे। यह सोच न्याय व्यवस्था को केवल प्रक्रिया आधारित तंत्र से निकालकर नागरिक-केंद्रित व्यवस्था में बदलने का प्रयास है। इन सुधारों में समयबद्ध न्याय की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले जांच एजेंसियों के पास निश्चित समय-सीमा का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र नहीं था। अब विभिन्न चरणों के लिए स्पष्ट समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं और तकनीकी माध्यमों से उनकी निगरानी की जा रही है। डिजिटल अलर्ट और केस ट्रैकिंग सिस्टम अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे जांच में अनावश्यक देरी कम होने की संभावना बढ़ी है और अदालतों तक मामलों के पहुंचने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो रही है। समय पर आरोप पत्र दाखिल होने से मुकदमों के शीघ्र निस्तारण का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

तकनीक का समावेश इन परिवर्तनों की सबसे बड़ी विशेषता है। ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डिजिटल समन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसी व्यवस्थाएं न्याय प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना रही हैं। अब नागरिकों को केवल कागजी औपचारिकताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। डिजिटल रिकॉर्ड के कारण दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं, उनकी सत्यता आसानी से प्रमाणित की जा सकती है और संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेजी से संभव हो पाता है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी की संभावनाएं भी कम होती हैं। वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देना भी इन सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक अपराधों की प्रकृति लगातार बदल रही है और केवल मौखिक गवाही के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना कई बार कठिन हो जाता है। इसलिए, गंभीर अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका को अनिवार्य बनाया गया है। मोबाइल फोरेंसिक वैन और आधुनिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से घटनास्थल से तुरंत वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। इससे जांच की गुणवत्ता में सुधार आता है और अदालतों के सामने अधिक विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य न्याय प्रक्रिया को मजबूत बनाने के साथ-साथ निर्दोष लोगों को गलत आरोपों से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एकीकृत डिजिटल न्याय प्रणाली इन सुधारों का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल प्रशासन और फोरेंसिक विभाग को एक साझा मंच पर जोड़ने के कार्य से पुनरावृत्ति कम होती है और सूचनाओं का प्रवाह तेज होता है। पहले जिस जानकारी को अलग-अलग विभागों में बार-बार दर्ज करना पड़ता था, अब उसे एक ही बार दर्ज करके सभी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाया जा सकता है।

पारिवारिक और सामाजिक पुनर्वास की मानवीय पहल

"देश के एक तिहाई जिलों पर लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहा नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के दावे के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देश तकरीबन नक्सलमुक्त हो चुका है। इस दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ज्यादातर बड़े नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं, या कई ने आत्मसमर्पण कर दिया है।"

अभी हाल ही में पिता दिवस गुजरा है। इस दिन सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर हुई चर्चाओं में एक बात प्रमुखता से छायी रही। ऐसा कहा गया कि पिता बनने के बाद लोगों की शख्सियत में बदलाव आ जाता है। चूंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लिहाजा इन दायित्वों के चलते कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी नरम हो जाता है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने जब पूर्व नक्सलियों की जबरिया कराई गई नसबंदी को खोलने वाले जटिल ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई, पता नहीं, उसके दिमाग में यह तथ्य था या नहीं। लेकिन उसकी इस कोशिश से कभी इंन्सानी खून से लाल रही बस्तर की धरती के कई आंगन किलकारियां गूंज रही हैं। देश के एक तिहाई जिलों पर लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहा नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के दावे के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देश तकरीबन नक्सलमुक्त हो चुका है। इस दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ज्यादातर बड़े नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं, या कई ने आत्मसमर्पण कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2700 नक्सली आत्म समर्पण कर चुके है। इन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहयोग के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें कई सारी योजनाएं चला रही हैं। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ और झारखंड में आर्थिक सहयोग, रोजगार, घर आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे नक्सलियों के पुनर्वास को गति मिली है। लेकिन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास कार्यक्रमों में एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। यह विशेष मुहिम सिर्फ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ही चला रही है। इस मुहिम को पारिवारिक और सामाजिक पुनर्वास कहा जा सकता है।

दरअसल नक्सली संगठनों में फील्ड कार्य कर रहे नक्सलियों के लिए अमानवीय प्रथा थी। फील्ड में काम कर रहे कम उम्र के नक्सलियों की अमानवीय तरीके से जबरिया नसबंदी करा दी जाती थी, ताकि नक्सली कार्य करते वक्त वे अपना परिवार न बढ़ा सकें। नक्सली संगठनों में महिला नक्सली भी सक्रिय थीं, उनके बीच रिश्ते पनपने संभव थे। लेकिन उन रिश्तों से बच्चे ना हों, इसलिए पुरूष नक्सलियों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। जिनमें बहुत सारे नक्सलियों की उम्र बेहद कम थी। लेकिन सरकारी मुहिम के बाद जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उनके मन में भी परिवार बसाने और अपने घर-आंगन में किलकारी गूंजने की चाहत जगी। चूंकि इनकी नसबंदी हो चुकी थी, लिहाजा इन्हें मन-मसोस कर रह जाना पड़ता था। छत्तीसगढ़ सरकार इन्हीं समर्पित प्रजनन उम्र वाले नक्सलियों के लिए पारिवारिक तौर पर ज्यादा सक्रिय होने के लिए यह मानवीय पहल शुरू की है।

पशुपति यानी नेपाल से लेकर तिरूपति यानी आंध्र के जंगली गलियारे तक तूती बोलने के दौर में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित था। खूंखार नक्सलियों के लिए कुख्यात इसी बस्तर संभाग से छत्तीसगढ़ सरकार ने मानवीय पहल शुरू की है। इसके तहत प्रजनन की उम्र वाले उन नक्सलियों का रिवर्स वैसेक्टॉमी शुरू किया है। नसबंदी करा चुके लोगों के लिए रिवर्स वासेक्टॉमी एक तरह से उनकी नसों को फिर से खोलने और उन्हें प्रजनन योग्य बनाने की जटिल प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने इस अनूठी पहल को यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की मदद से शुरू किया है। 14 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, दो चरणों में 73 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने का ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। पहले चरण में 33 पूर्व नक्सलियों को खुशहाल जिंदगी गुजारने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो दूसरे चरण में 40 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी को खोला गया। पहले चरण में जिन 33 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, उनमें से 27 के आंगन किलकारियों से गूंज रहे हैं। बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के अनुसार, बस्तर के एक पूर्व नक्सली के घर दो महीने पहले ही बच्ची का जन्म हो चुका है। उस पूर्व नक्सली का परिवार इस बच्ची के साथ अपना पारिवारिक जीवन आनंद से बिता रहा है।

आमतौर नसबंदी खोलने के इस जटिल ऑपरेशन के लिए बड़े शहरों और महानगरों के सुविधा संपन्न अस्पतालों में जाना पड़ता है। लेकिन यह पहला मौका है, जब छत्तीसगढ़ के दूर-दराज के बस्तर संभाग में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इस जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया को सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। इस पहल में बस्तर के जिला प्रशासन के साथ ही बस्तर पुलिस और यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के पश्चिमी जोन की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंदौर निवासी डॉक्टर राजेश कुकरेजा का कहना है कि बस्तर जैसे इलाके में इतने बड़े स्तर पर नसबंदी खोलने का सफल ऑपरेशन किया जाना चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। इस ऑपरेशन की शुरूआत जगदलपुर के महारानी अस्पताल में की गई। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। जगदलपुर के जिला अस्पताल में नसबंदी खोलने के विशेष शिविरों में देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुशील राठी, डॉ. ललित शाह एवं डॉ. योगेश बरापात्रे सहित इंदौर के डॉ. राजेश कुकरेजा, पुणे के डॉ. सागर भालेराव और डॉ. राहुल, महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉ. अभिषेक, मुंबई के डॉ. निनाद तंबोली और डॉ. पार्थ मानेक के साथ ही रायपुर के डॉ. राहुल कपूर एवं डॉ. घनश्याम हटवार की टीम ने पूर्व नक्सिलियों का सफल ऑपरेशन किया है। इनके सहयोग के लिए छह स्थानीय डॉक्टरों सहित करीब 50 सदस्यों वाली मेडिकल टीम जुटी रही।

भौगोलिकसंदर्भ

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल बाकी राज्यों द्वारा नक्सलियों के आर्थिक और जमीनी पुनर्वास नीति से अलग है। विष्णुदेव साय सरकार की इस मानवीय पहल की प्रशंसा मेडिकल जगत के साथ ही समाजविज्ञानी भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत शारीरिक और मेडिकल जांच के साथ ही प्रजनन योग्य पाए जाने वाले नक्सलियों के ही ऑपरेशन किए जाते हैं। इनमें चालीस साल तक की उम्र वाले पूर्व नक्सलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद के मुताबिक, राज्य सरकार की पहल पर जल्द ही तीसरे चरण का भी शिविर लगाने की तैयारी है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा पूर्व नक्सलियों के ऑपरेशन किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ की यह मानवीय पहल समर्पित नक्सलियों को ना सिर्फ अपने समाज, बल्कि परिवार से भी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा रणनीति से आगे बढ़कर विश्वास निर्माण और सामाजिक-मानवीय पुनर्वास मॉडल के रूप में आगे आ रहा है। ये 73 ऑपरेशन महज चिकित्सकीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि इन परिवारों की उम्मीद और सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ने का भी प्रतीक है।

प्रेरणा

जब साहित्य समाज का आईना बन जाता है

साहित्य का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी संवेदनाओं को जगाना, समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाना और पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करना भी होता है। जब कोई लेखक अपने जीवनानुभव, सामाजिक निरीक्षण और मानवीय संवेदनाओं को सरल शब्दों में प्रस्तुत करता है, तब उसकी रचना केवल कहानी नहीं रहती, बल्कि समय का दस्तावेज बन जाती है। ऐसी ही अनुभूति उस साहित्य से होती है, जिसमें जीवन के छोटे-छोटे प्रसंगों के माध्यम से बड़े सामाजिक और नैतिक प्रश्न उठाए जाते हैं। शब्दों का अनावश्यक आडंबर, जटिल भाषा और कृत्रिम कथानक पाठक को क्षणिक आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन जो साहित्य सीधे मन और विवेक को स्पर्श करता है, वही लंबे समय तक स्मृतियों में जीवित रहता है। यही विशेषता उन रचनाओं में दिखाई देती है जो लघुकथा, संस्मरण और व्यंग्य की विधाओं को एक साथ लेकर चलती हैं और जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी बनावट के सामने रखती हैं। आज के समय में साहित्य की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बदलते समाज की जटिलताओं को किस प्रकार अभिव्यक्त करे। आधुनिक जीवन ने मनुष्य को सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन उसके भीतर का अकेलापन, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और दिखावा भी बढ़ाया है। ऐसे दौर में यदि कोई लेखक केवल घटनाओं का वर्णन करने के बजाय उनके पीछे छिपे सामाजिक अर्थों को उजागर करता है, तो उसकी रचना अधिक प्रभावशाली बन जाती है। छोटी-सी घटना, साधारण संवाद या सामान्य प्रतीत होने वाला अनुभव भी यदि संवेदनशील दृष्टि से देखा जाए, तो वह पूरे समाज का चरित्र उजागर कर सकता है। यही साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति है कि वह कम शब्दों में भी गहरे अर्थ समेट सकता है। लघुकथा की विधा विशेष रूप से इसी कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीमित शब्दों में व्यापक जीवन-दर्शन प्रस्तुत करना आसान नहीं होता। एक सफल लघुकथा वही है जो पढ़ने के बाद समाप्त नहीं होती, बल्कि पाठक के भीतर विचारों का सिलसिला शुरू कर देती है। जब इसमें संस्मरण की आत्मीयता और व्यंग्य की तीक्ष्णता भी जुड़ जाए, तब रचना का प्रभाव और अधिक व्यापक हो जाता है। पाठक केवल घटनाओं का साक्षी नहीं रहता, बल्कि स्वयं उन परिस्थितियों का हिस्सा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि ऐसी रचनाएं किसी एक विधा की सीमाओं में बंधी हुई नहीं दिखाई देतीं, बल्कि अनेक साहित्यिक रूपों का सुंदर संगम बन जाती हैं। समाज की विडंबनाओं पर लिखना हमेशा आसान नहीं होता। लेखक को अनेक बार उन विषयों को छूना पड़ता है, जिन पर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। धर्म के नाम पर बढ़ता दिखावा, आस्था का व्यापार, सामाजिक असमानताएं, नैतिक मूल्यों का क्षरण, राजनीतिक स्वार्थ और मानवीय संवेदनाओं का ह्रास जैसे विषय किसी भी संवेदनशील लेखक को विचलित करते हैं। यदि लेखक इन प्रश्नों को ईमानदारी से उठाता है, तो उसकी लेखनी केवल आलोचना नहीं करती, बल्कि समाज को स्वयं का चेहरा देखने के लिए बाध्य भी करती है। व्यंग्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का उपहास करना नहीं होता, बल्कि उन प्रवृत्तियों पर चोट करना होता है जो समाज को भीतर से खोखला कर रही होती हैं। आज धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बीच का अंतर भी धीरे-धीरे धुंधला होता जा रहा है। बाहरी आडंबर, बड़े-बड़े आयोजन, महंगे धार्मिक समारोह और दिखावटी भक्ति कई बार वास्तविक मानवीय मूल्यों पर भारी पड़ जाते हैं। जब कोई लेखक इन प्रवृत्तियों पर प्रश्न उठाता है, तो उसका उद्देश्य आस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि आस्था के नाम पर फैल रही विसंगतियों को उजागर करना होता है। सच्चा धर्म मनुष्य को विनम्र, करुणामय और ईमानदार बनाता है, जबकि दिखावटी धार्मिकता अक्सर अहंकार, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। साहित्य का दायित्व यही है कि वह इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करे और पाठक को बाहरी चमक-दमक से परे वास्तविक मूल्यों की ओर लौटने का संदेश दे। लेखक की सबसे बड़ी सफलता तब मानी जाती है जब वह उपदेश दिए बिना पाठक को सोचने के लिए विवश कर दे। सीधे-सीधे नैतिक शिक्षा देने के बजाय यदि कोई रचनाकार छोटे-छोटे प्रसंगों, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहता है, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। पाठक स्वयं निष्कर्ष निकालता है और वही निष्कर्ष उसके मन में लंबे समय तक बना रहता है। यही कारण है कि संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित रचनाएं कई बार लंबे उपन्यासों से अधिक प्रभाव छोड़ जाती हैं। उनमें शब्द कम होते हैं, लेकिन अर्थ अनंत होते हैं। संस्मरणात्मक शैली ऐसी रचनाओं को आत्मीयता प्रदान करती है। जब लेखक अपने जीवन के अनुभवों, देखी-सुनी घटनाओं और सामाजिक अवलोकनों को सहज भाषा में प्रस्तुत करता है, तो पाठक को उनमें कृत्रिमता नहीं दिखाई देती। उसे लगता है कि यह कहानी किसी काल्पनिक संसार की नहीं, बल्कि उसके अपने आसपास की है। यही आत्मीयता साहित्य को जीवन के अधिक निकट ले आती है। लेखक का अनुभव व्यक्तिगत होते हुए भी सामूहिक बन जाता है, क्योंकि उसमें समाज की साझा पीड़ा, संघर्ष और उम्मीदें झलकती हैं। व्यंग्य की शक्ति उसकी मारकता में नहीं, बल्कि उसकी सार्थकता में होती है। श्रेष्ठ व्यंग्य वही है जो मुस्कुराने के साथ-साथ असहज भी कर दे। वह केवल हंसी पैदा नहीं करता, बल्कि भीतर छिपे प्रश्नों को जगाता है। समाज में फैले भ्रष्टाचार, अवसरवाद, पाखंड और दोहरे चरित्र पर यदि व्यंग्य न हो, तो साहित्य अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका खो देगा। व्यंग्यकार उन बातों को कहने का साहस करता है जिन्हें सामान्य भाषा में कहना कठिन होता है। उसकी लेखनी तलवार की तरह नहीं, बल्कि दर्पण की तरह काम करती है, जिसमें समाज स्वयं को पहचानने लगता है। वर्तमान समय में जब सोशल मीडिया और त्वरित सूचना के युग ने पढ़ने की आदतों को बदल दिया है, तब लघु साहित्यिक विधाओं का महत्व और भी बढ़ गया है। पाठक अब कम समय में सार्थक और विचारोत्तेजक साहित्य पढ़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में लघुकथा, संस्मरण और व्यंग्य का संयोजन नई पीढ़ी के पाठकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यदि भाषा सरल हो, कथ्य प्रभावशाली हो और विचार प्रासंगिक हों, तो छोटी-सी रचना भी बड़े विमर्श को जन्म दे सकती है। यही कारण है कि आज संक्षिप्त साहित्यिक अभिव्यक्तियां भी गंभीर साहित्यिक चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि वह कितने पाठकों तक पहुंचा, बल्कि यह है कि उसने कितने मनों को बदलने का प्रयास किया। जो रचना पाठक को अपने व्यवहार, सोच और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, वही वास्तव में सफल कही जा सकती है। शब्दों की सादगी, विचारों की गहराई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी किसी भी साहित्यिक कृति को कालजयी बनाने के लिए पर्याप्त होती है।

चीन प्लस-वन का विकल्प बनता यूपी

किसी राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब एक अकेला निर्णय न केवल भूगोल को, बल्कि समूची नियति को बदल देता है। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और व्यावसायिक उड़ानों का शुभारंभ निःसंदेह ऐसा ही एक क्षण है, लेकिन इसे केवल एक हवाई अड्डा कहना भूल होगी। भू-अर्थशास्त्र की दृष्टि से जेवर महज एक अवसंरचना नहीं, एक घोषणापत्र है, जो भूगोल, आर्थिक शक्ति और भू-राजनीतिक रणनीति का संगम है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो सदियों से अपनी भूबद्ध स्थिति की बेड़ियों में जकड़ा रहा, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के द्वार पर दस्तक दे रहा है।

24 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य जनसंख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, लेकिन समुद्री व्यापार मार्गों तक उसकी सीधी पहुंच नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डा उद्घाटन के अवसर पर इसी सच्चाई को रेखांकित किया कि यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की भूबद्ध बाधाओं को तोड़कर राज्य के एमएसएमई, कृषि और भारी उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। जेवर का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने जो कहा, वह भू-आर्थिक सोच का संक्षिप्त सार है कि यह सिर्फ एक हवाई अड्डा ही नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास का प्रवेश द्वार है।

भू-अर्थशास्त्र के सिद्धांत यह स्थापित करते हैं कि किसी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का मार्ग उसकी भौगोलिक बनावट से होकर गुजरता है। अभी जेवर हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्री और 2.5 लाख टन कार्गो की है, जो अंततः सात करोड़ यात्री और 10 लाख टन कार्गो तक विस्तृत होगी। यह हवाई अड्डा राज्य को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़कर उसकी भूबद्ध बाधाओं को पार करने में मदद करेगा। जेवर को साधारण हवाई अड्डे से अलग करने वाली बात उसकी एरोट्रोपोलिस परिकल्पना है। एअर इंडिया एसएटीएस द्वारा संचालित मल्टी-माडल कार्गो हब, वाईईआईडीए सेक्टर-10 में 206 एकड़ का इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 3,706 करोड़ रुपये का एचसीएल-फाक्सकान सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम नोएडा से जेवर तक यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक नए औद्योगिक हब की नसें हैं। वाईईआईडीए की एफडीआई और फार्च्यून-500 नीति के तहत अब तक आठ कंपनियों ने इस गलियारे में लगभग 12,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

सेमीकंडक्टर संयंत्र का महत्व विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। यहां बनने वाली चिप मोबाइल फोन, लैपटाप और आटोमोबाइल को संचालित करेंगी, वही उत्पाद जो वैश्विक चीन-प्लस-वन आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण के केंद्र में हैं। नोएडा में सैमसंग का विश्वस्तरीय विनिर्माण केंद्र, हैवेल्स, अंबर एंटरप्राइजेज, माइक्रोसाफ्ट और एचसीएल-फाक्सकान की उपस्थिति से यह गलियारा उत्तर भारत में चीन-प्लस-वन रणनीति का प्राथमिक केंद्र बन चुका है। कार्गो हब का लक्ष्य है कि भारत को, विशेषकर उसके उत्तरी क्षेत्र को, वैश्विक लाजिस्टिक्स का प्रमुख प्रवेशद्वार और चीन-प्लस-वन रणनीति का विश्वसनीय विकल्प बनाया जाए। भारत के पहले एकीकृत एमआरओ केंद्र के रूप में भी जेवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। दशकों से भारतीय एयरलाइंस विमानों के रखरखाव के लिए सिंगापुर और दुबई पर निर्भर रही हैं। आने वाले समय में दुनिया भर के लोग इन सेवाओं के लिए जेवर आएंगे। जेवर कृषि के लिए भी उतना ही क्रांतिकारी है। फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद और सजावटी फूल अब सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे। इससे किसानों की आय में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर जेवर मेक इन इंडिया, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन और राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स नीति तीनों को एक साथ गति देता है। 50,000 प्रत्यक्ष और 50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार, फिल्म सिटी, खिलौना पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और डाटा सेंटर का पूरा इकोसिस्टम आज उत्तर प्रदेश और एनसीआर को एक नई वैश्विक पहचान दे रहा है। जेवर हवाई अड्डा एक दिन में नहीं बना है, यह अथक भूमि अधिग्रहण, नीतिगत नवाचार, निवेशक कूटनीति और दूरदर्शी राजनीतिक साहस का सम्मिलित परिणाम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब शासन की बागडोर संभाली थी तब उत्तर प्रदेश देश के तीन सबसे पिछड़े राज्यों में था। आज राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये के संचयी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2016-17 के 71,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में देश में सर्वाधिक 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षा की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को पांच लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश भी एक लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लेता है।' यह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, एक सभ्यतागत संकल्प है। जेवर उस संकल्प की उड़ान पट्टी है। और इतिहास साक्षी है कि-जब उड़ान पट्टी तैयार होती है, तो स्वप्न भी उड़ान भरते हैं।

अभियान

सुंदरकांड की चौपाइयाँ: केवल पाठ नहीं, सफल और संतुलित जीवन का दिव्य विज्ञान

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। रामचरितमानस उनमें सर्वोच्च स्थान रखता है, क्योंकि इसमें वर्णित प्रसंग केवल भगवान श्रीराम के जीवन का वर्णन नहीं करते, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों, संघर्षों और सफलताओं का भी गहन दर्शन कराते हैं। इन्हीं प्रसंगों में सुंदरकांड को विशेष रूप से आशा, साहस, आत्मविश्वास और विजय का प्रतीक माना जाता है। सदियों से यह विश्वास रहा है कि सुंदरकांड का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से संकट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किंतु यदि इसके गूढ़ संदेश को समझा जाए तो स्पष्ट होता है कि इसकी चौपाइयाँ केवल धार्मिक अनुष्ठान का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य को मानसिक दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता, धैर्य, आत्मसंयम और लक्ष्य प्राप्ति का अद्भुत सूत्र भी प्रदान करती हैं।

आज का युग अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों का भी युग है। प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है, अपेक्षाएँ ऊँची होती जा रही हैं और असफलता का भय पहले की तुलना में अधिक गहरा होता जा रहा है। विद्यार्थी बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, युवा रोजगार और करियर की चिंता में है, व्यवसायी आर्थिक उतार-चढ़ाव से जूझ रहा है और परिवार का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी मानसिक दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे समय में केवल बाहरी संसाधन पर्याप्त नहीं होते। सफलता के लिए मानसिक संतुलन, धैर्य, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक होती है। सुंदरकांड की चौपाइयाँ मनुष्य को इन्हीं गुणों से समृद्ध करने का प्रयास करती हैं।

सुंदरकांड का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही विद्यमान होती है। अधिकांश लोग अपनी सीमाओं को तो पहचानते हैं, लेकिन अपनी संभावनाओं को नहीं। भय, संदेह और निराशा उनके आत्मविश्वास को धीरे-धीरे कमजोर कर देते हैं। हनुमान जी का चरित्र इसी सत्य का प्रतीक है। वे अपार बल, ज्ञान और क्षमता के स्वामी होते हुए भी अपनी शक्ति को विस्मृत कर चुके थे। जब जाम्बवान ने उन्हें उनकी वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण कराया, तभी वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हुए। यह प्रसंग केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का गहरा सिद्धांत है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अद्भुत संभावनाएँ छिपी होती हैं, जिन्हें जागृत करने के लिए आत्मविश्वास और सही प्रेरणा की आवश्यकता होती है।

इसी संदर्भ में सुंदरकांड की प्रसिद्ध चौपाई—

"कवन सो काज कठिन जग माहीं।
जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥
राम काज लगि तव अवतारा।
सुनतहिं भयउ पर्बताकारा॥"

जीवन का अत्यंत प्रेरक संदेश देती है। यह चौपाई केवल हनुमान जी की प्रशंसा नहीं करती, बल्कि हर मनुष्य को यह विश्वास दिलाती है कि यदि उसका उद्देश्य श्रेष्ठ हो, मन निर्मल हो और प्रयास निरंतर हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यह हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह अवसर मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह सीमित संसाधनों में भी असाधारण उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है।

इसी प्रकार दूसरी प्रसिद्ध चौपाई—

"प्रबिसि नगर कीजे सब काजा।
हृदय राखि कोसलपुर राजा॥
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई।
गोपद सिंधु अनल सितलाई॥"

जीवन के व्यवहारिक दर्शन का अद्भुत उदाहरण है। सामान्यतः इसे कार्य सिद्धि की चौपाई माना जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसका संदेश यह है कि जब मनुष्य अपने हृदय में श्रीराम के आदर्शों—सत्य, मर्यादा, करुणा, धैर्य और धर्म—को स्थापित करता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। परिस्थितियाँ वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक दृष्टि ले लेती है। कठिनाइयाँ अवसर बनने लगती हैं, शत्रुता संवाद में बदल सकती है और बड़े संकट भी धीरे-धीरे छोटे दिखाई देने लगते हैं। यही मानसिक परिवर्तन व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है।

यदि इन चौपाइयों को केवल चमत्कार की दृष्टि से देखा जाए तो उनका वास्तविक महत्व कम हो जाएगा। सुंदरकांड का संदेश भाग्यवाद नहीं, बल्कि पुरुषार्थ है। हनुमान जी ने केवल प्रभु का स्मरण नहीं किया, बल्कि अथक परिश्रम भी किया। उन्होंने समुद्र लांघा, सुरसा की परीक्षा पार की, सिंहिका का सामना किया, लंका में प्रवेश किया, माता सीता की खोज की, रावण के दरबार में निर्भीक होकर संदेश दिया और अंत में सुरक्षित लौटकर पूरी जानकारी श्रीराम तक पहुँचाई। यह संपूर्ण यात्रा इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर पर विश्वास और कर्मठता साथ-साथ चलें, तभी सफलता मिलती है।

आधुनिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। विद्यार्थी यदि केवल सुंदरकांड का पाठ करे लेकिन पढ़ाई न करे, तो सफलता संभव नहीं। व्यापारी यदि केवल पूजा करे लेकिन ईमानदार व्यापार न करे, तो उन्नति कठिन होगी। नौकरी की तैयारी करने वाला युवक यदि केवल प्रार्थना करे लेकिन नियमित अभ्यास न करे, तो उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। सुंदरकांड स्पष्ट रूप से बताता है कि ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो स्वयं भी पूरे समर्पण से अपने कर्तव्य का पालन करता है।

सुंदरकांड का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। आज चिंता, तनाव, अवसाद और असुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ रही है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने मनुष्य को भीतर से थका दिया है। ऐसे समय में नियमित पाठ, ध्यान और प्रार्थना मन को स्थिर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सुंदरकांड का शांत और प्रेरणादायक वाचन मन में सकारात्मक विचारों का संचार करता है। इससे आत्मबल बढ़ता है, भय कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक शब्दों का नियमित उच्चारण मानसिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हनुमान जी का चरित्र नेतृत्व का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे केवल शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि अत्यंत विवेकशील भी थे। उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को बदला। जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ बल का प्रयोग किया, जहाँ संवाद आवश्यक था वहाँ विनम्रता दिखाई और जहाँ धैर्य की आवश्यकता थी वहाँ संयम रखा। आधुनिक प्रबंधन विज्ञान भी यही सिखाता है कि सफल नेता वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके। इस दृष्टि से सुंदरकांड नेतृत्व कौशल का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है।

इसके साथ ही सुंदरकांड विनम्रता का भी अप्रतिम संदेश देता है। इतनी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त करने के बाद भी हनुमान जी ने कभी स्वयं को महान नहीं बताया। उन्होंने हर सफलता का श्रेय श्रीराम को दिया। आज जब छोटी-सी सफलता भी कई लोगों में अहंकार उत्पन्न कर देती है, तब हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि वास्तविक महानता उपलब्धियों में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक सफल होता है, उसे उतना ही अधिक संयम और सरलता अपनानी चाहिए।

सुंदरकांड यह भी सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हनुमान जी का उद्देश्य केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं था। उनका एक निश्चित लक्ष्य था और उसी पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहा। आज अनेक लोग अपनी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखेर देते हैं, जिसके कारण वे किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाते। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।

नियमित सुंदरकांड पाठ का एक और लाभ यह है कि यह व्यक्ति के भीतर अनुशासन विकसित करता है। प्रतिदिन निश्चित समय पर पाठ करने की आदत जीवन में नियमितता लाती है। यही नियमितता धीरे-धीरे कार्यशैली, समय प्रबंधन और व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। अनुशासन ही दीर्घकालीन सफलता की नींव है और सुंदरकांड अप्रत्यक्ष रूप से इसी जीवन मूल्य को मजबूत करता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए नया 'वैज्ञानिक हथियार' बनीं मोबाइल फॉरेंसिक वैन : दो वर्ष में 37 हजार से अधिक क्राइम सीन पर पहुंचीं

▶▶ गुजरात में 47 फॉरेंसिक वैन कार्यरत, क्राइम सीन पर 'ऑन द स्पॉट' प्राथमिक परीक्षण करने के लिए तैयार
▶▶ सबूतों को नष्ट होने से बचाने, प्रक्रिया को तेज करने और जांच को गति देने के लिए मिनी फॉरेंसिक लेबोरेटरी

गांधीनगर : जब पुलिस किसी भी अपराध की जांच करती है, तब यह आवश्यक है कि सबूत समय पर इकट्ठा किए जाएं, और साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनमें किसी भी प्रकार की मिलावट या अशुद्धिकरण (कंटेमिनेशन) यानी छेड़छाड़ न हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुजरात में 47 मोबाइल फॉरेंसिक वैन (एमएफवी) पुलिस जांच में सहयोग के लिए कार्यरत हैं। ये फॉरेंसिंक वैन यह सुनिश्चित करती हैं कि अपराध स्थल पर सबूतों को जल्द से जल्द सुरक्षित रखा जाए, उनकी प्राथमिक जांच समय पर हो जाए तथा शुरुआती फॉरेंसिक राय मिल जाए, ताकि त्वरित पुलिस जांच में मदद मिल सके। राज्य में फॉरेंसिक विज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूरदर्शी सोच के साथ गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (जीएसएफयू) की स्थापना की थी, जिसे अब केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। पुलिस के कामकाज और कानून व्यवस्था बनाए रखने में फॉरेंसिक विज्ञान का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके विजनरी मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समयानुकूल नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में दोषसिद्धि दर (सजा की दर) को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से अपराधों की जांच को विशेष महत्व दिया गया है। इन कानूनों के लागू होने से 7 साल से अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बना दिया गया है, ऐसे में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका और भी बढ़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री के विजन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।

37 हजार से अधिक क्राइम सीन पर पहुंचीं मोबाइल फॉरेंसिक वैन

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2024 में 47 में से 28 मोबाइल फॉरेंसिक वैन (एमएफवी) को अपग्रेड किया गया। गत दो वर्षों में एमएफवी 37,269 क्राइम सीन/स्पॉट पर पहुंची हैं। एमएफवी ने हत्या, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो), लूट, चोरी, आगजनी और नारकोटिक्स सहित अन्य महत्वपूर्ण अपराधों के मामलों में घटनास्थल पर सहायता प्रदान की है। अलग-अलग क्राइम सीन यानी घटनास्थलों के दौरों में मिले अपराधवार आंकड़ें इस प्रकार है : हत्या (1529), बलात्कार/पॉक्सो/बच्चों के साथ दुर्व्यवहार (3746), हत्या का प्रयास (1583), लूट (728), सेंधमारी/चोरी (2758), गोलीबारी (154), विस्फोट (43), आगजनी 92893), नारकोटिक्स (1968) और फेटल-जानलेवा मामले (9022)। इसके अलावा, 10,457 अन्य घटनास्थल के दौरों में आकस्मिक मौत, हिरासत में मौत, अप्राकृतिक मौत, संदिग्ध घटनाओं और दूसरी कानून व्यवस्था से जुड़ी फॉरेंसिक जांच शामिल हैं।

चलती-फिरती फॉरेंसिक लेबोरेटरी, अलग-अलग अपराधों के लिए है

अलग-अलग किट

इन मोबाइल फॉरेंसिक वैनों में 12 विशेष वैज्ञानिक किट उपलब्ध हैं। जिनमें डीएनए और सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े सबूतों की किट, नारकोटिक्स स्क्रीनिंग किट, एक्सप्लोसिव स्क्रीनिंग किट, गन शॉट रेसिड्यू किट, आगजनी की जांच के लिए किट, फुट प्रिंट और टायर प्रिंट कास्टिंग किट सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

इन वाहनों में स्टीरियो माइक्रोस्कोप, डीएसएलआर कैमरा, जीपीएस वाले बॉडी-वॉर्न कैमरा सिस्टम, लैपटॉप और प्रिंटर, मिनी रेफ्रिजरेटर, एलईडी स्क्रीन, हाई इंटेंसिटी फॉरेंसिक लाइट सोर्स, जनरेटर सेट और अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं। इन उपकरणों की मदद से अपराध स्थल पर ही विभिन्न सबूतों जैसे खून के धब्बे और अन्य जैविक नमूने, फिंगरप्रिंट्स, पैरों और टायर के निशान, गन शॉट रेसिड्यू, नारकोटिक्स पदार्थ, विस्फोटक अवशेष, जली हुई सामग्री, बाल, फाइबर, मिट्टी के नमूने और कांच के टुकड़े सहित अन्य सूक्ष्म सबूतों की शुरुआती जांच की जा सकती है।

तेज जांच और मजबूत सबूत

मोबाइल फॉरेंसिक वैन का मुख्य उद्देश्य अपराध स्थल पर तत्काल वैज्ञानिक सहायता देना, सबूतों को उचित तरीके से सुरक्षित रखना, सबूत दूषित होने की संभावना को कम करना और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करना है। विशेषकर, बलात्कार और पॉक्सो के मामलों में जैविक सबूतों की समय पर पहचान करना और सबूतों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में इस वैन की भूमिका काफी अहम हो जाती है। बॉडी कैमरा, डीएसएलआर फोटोग्राफी और सीसीटीवी आधारित दस्तावेजीकरण के कारण क्राइम सीन का वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन भी अधिक प्रभावी हो गया है।

आज, आपराधिक जांच वैज्ञानिक सबूतों पर अधिक से अधिक निर्भर हो रही है, इसलिए गुजरात में मोबाइल फॉरेंसिक वैन अपराधों की जांच-पड़ताल करने के तरीके को बदल रहे हैं। इस प्रकार, फॉरेंसिक विज्ञान सीधे घटनास्थल पर पहुंचता है, अहम सबूतों को सुरक्षित रखता है और फर्स्ट रिस्पॉन्स से लेकर अंतिम निर्णय आने तक मजबूत केस बनाने में मदद करता है।

मंडल रेल प्रबंधक ने भावनगर-धोला एवं खिजड़िया–धोला रेलखंड का किया व्यापक संरक्षा निरीक्षण और जनप्रतिनिधियों के साथ रेल विकास पर की समीक्षा बैठक

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने 02 जुलाई, 2026 को भावनगर–धोला रेलखंड, खिजड़िया–धोला रेलखंड, धोला स्टेशन एवं अमरेली स्टेशन का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं, स्टेशन विकास, रेल संरक्षा, स्वच्छता तथा प्रगति पर चल रही विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, प्लेटफॉर्म सुधार कार्यों, संरक्षा उपायों तथा अन्य विकास परियोजनाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए, ताकि यात्रियों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत अमरेली क्षेत्र के माननीय कानून, न्याय, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री, गुजरात सरकार श्री कौशिकभाई कांतिभाई वेकरिया एवं माननीय सांसद श्री भरतभाई सुतरिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार, यात्री आवश्यकताओं तथा विभिन्न विकासात्मक विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विकास कार्यों में रेल संरक्षा को सर्वोच्च महत्व देने, गुणवत्ता मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा परियोजनाओं की नियमित एवं प्रभावी निगरानी करने पर विशेष बल दिया।

उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे आपसी समन्वय, टीम भावना, उत्तरदायित्व एवं कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भावनगर मंडल को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्रिय योगदान दें।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे-2026 गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल स्थित मंडलीय रेलवे चिकित्सालय (DRH) में 01 जुलाई, 2026 को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे-2026 का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार के नेतृत्व में अत्यंत गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना था।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि समारोह का आयोजन दो चरणों में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के लगभग 70 सदस्यों ने मंडलीय रेलवे चिकित्सालय का भ्रमण कर सभी चिकित्सकों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रत्येक चिकित्सक को स्मृति-चिह्न भेंट कर उनके समर्पित, निस्वार्थ एवं मानवीय सेवाभाव के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए तथा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। यह अवसर समाज द्वारा चिकित्सकों के प्रति सम्मान, विश्वास एवं आस्था का प्रेरणादायी उदाहरण बना।

समारोह के द्वितीय चरण में मंडलीय रेलवे चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से डॉक्टर्स डे समारोह में भाग लिया। इस दौरान टीम भावना एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु मेडिकल डम्ब शराड्स (Medical Dumb Charades) तथा रैपिड फायर मेडिकल क्विज (Rapid Fire Medical Quiz) जैसी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, खेल भावना एवं आपसी सहयोग के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण, सहयोगात्मक एवं पारिवारिक वातावरण देखने को मिला।

समारोह के समापन अवसर पर चिकित्सकों द्वारा मानव सेवा के प्रति प्रदर्शित समर्पण, रोगियों के प्रति संवेदनशीलता तथा उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं की सराहना की गई। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन, सामूहिक छायाचित्र एवं जलपान के साथ हुआ।

इस अवसर पर यह संदेश भी साझा किया गया कि—"चिकित्सक केवल रोगों का उपचार नहीं करते, वे आशा, विश्वास और जीवन का संचार करते हैं।" राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के इस आयोजन ने चिकित्सकों के प्रति सम्मान, सेवा भावना एवं मानवता के मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश दिया।

वडोदरा मंडल द्वारा प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत विद्या मंदिर, प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में पल्स पोलियो टीकाकरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पाँच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने हेतु ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) की खुराक प्रदान करना था।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शिविर में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाई। स्वास्थ्य इकाई के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों ने बच्चों का टीकाकरण करने के साथ-साथ अभिभावकों को पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूक भी किया।

अभियान के दौरान अभिभावकों को बताया गया कि भारत भले ही पोलियो मुक्त हो, किन्तु पड़ोसी देश पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस अभी भी सक्रिय है। अंतरराष्ट्रीय आवागमन के कारण इसके पुनः फैलने की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान पाँच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, पूर्व में टीकाकरण हो चुका होने पर भी, ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंदें अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ बनी रहे और देश पोलियो मुक्त बना रहे।

वडोदरा मंडल का चिकित्सा विभाग बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य अभियानों के सफल संचालन हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णयः वकील की फीस 'अपराध की आय' नहीं है, खाता फ्रीज करना अनुचित है

नई दिल्ली। भारत का निजी कर्ज (प्राइवेट क्रेडिट) बाजार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गति से विकसित हुआ है और अब यह देश की वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी Moody's Ratings की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत का निजी कर्ज बाजार लगभग दोगुना होकर वर्ष 2025 के अंत तक करीब 25 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में तेजी से बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं, मजबूत आर्थिक गतिविधियों और पूंजी की बढ़ती मांग के कारण आने वाले वर्षों में भी इस क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। मूडीज का कहना है कि भारत में निजी कर्ज बाजार अब केवल उन कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया है, जो वित्तीय संकट से जूझ रही हैं या पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र का स्वरूप तेजी से बदला है और अब आर्थिक रूप से मजबूत तथा विस्तार की योजना बना रही कंपनियां भी निजी ऋणदाताओं के माध्यम से पूंजी जुटाने को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे यह क्षेत्र कॉरपोरेट वित्तपोषण के एक वैकल्पिक और प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित होता जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान निजी कर्ज बाजार में कुल सौदों का वार्षिक मूल्य 11 अरब डॉलर से अधिक रहा। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि कंपनियां पारंपरिक बैंक ऋण के अलावा निजी निवेशकों और वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों से भी बड़े पैमाने पर पूंजी जुटा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजनाओं के तेजी से विस्तार, अधिग्रहण, बुनियादी ढांचा विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की बढ़ती जरूरतों ने इस बाजार को नई गति प्रदान की है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल ही में Reserve Bank of India द्वारा लागू किए गए नए नियामकीय प्रावधान इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकते हैं। एक जुलाई से प्रभावी नए नियमों के तहत बैंकों को निर्धारित शर्तों के साथ रणनीतिक अधिग्रहणों और कुछ विशेष प्रकार के कॉरपोरेट सौदों के लिए वित्त उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। पहले जिन क्षेत्रों में निजी ऋणदाता प्रमुख भूमिका निभाते थे, वहां अब बैंक भी अधिक सक्रिय हो सकेंगे। इससे कंपनियों के पास वित्त जुटाने के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। मूडीज का आकलन है कि इन नए प्रावधानों का सबसे बड़ा लाभ उधार लेने वाली कंपनियों को मिलेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उन्हें अपेक्षाकृत कम लागत पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा और वित्त जुटाने की प्रक्रिया भी अधिक लचीली बनेगी। विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ब्याज दरों और ऋण की शर्तों में भी सुधार की संभावना है, जिससे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके विपरीत रिपोर्ट में निजी ऋणदाताओं के लिए कुछ चुनौतियों की ओर भी संकेत किया गया है। मूडीज का कहना है कि बैंकों की बढ़ती भागीदारी के कारण निजी ऋणदाताओं के लाभांश (मार्जिन) पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा रणनीतिक अधिग्रहणों और बड़े कॉरपोरेट सौदों में उनकी हिस्सेदारी कम होने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में निजी ऋणदाताओं को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने उत्पादों, सेवाओं और ऋण संरचनाओं को अधिक आकर्षक बनाना होगा। रिपोर्ट में भारत के निजी कर्ज बाजार की संरचना का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार इस बाजार का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता इस क्षेत्र को निजी ऋण बाजार का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनाती है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, औद्योगिक परियोजनाएं, सेवा क्षेत्र तथा अन्य उभरते उद्योग भी निजी कर्ज बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देश में शहरीकरण की बढ़ती गति, औद्योगिक निवेश और नई परियोजनाओं के कारण इन क्षेत्रों में वित्त की मांग लगातार बढ़ रही है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत विकास दर, निवेश-अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ते सरकारी तथा निजी निवेश के कारण निजी कर्ज बाजार की भूमिका आने वाले वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए, जिन्हें शीघ्र वित्तपोषण या लचीली ऋण संरचना की आवश्यकता होती है, निजी कर्ज बाजार एक प्रभावी विकल्प बनता जा रहा है।

रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ पूंजी की मांग लगातार बढ़ेगी। यदि नियामकीय संतुलन और वित्तीय स्थिरता बनी रहती है, तो निजी कर्ज बाजार न केवल आकार में और बड़ा होगा, बल्कि कॉरपोरेट वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। हालांकि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण इस क्षेत्र के प्रतिभागियों को बदलते बाजार और नियामकीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीतियों में निरंतर सुधार करना होगा।

कनॉट पैलेस में बांसुरी बजाते एक बुजुर्ग का भावुक वीडियो वायरल हो गया है, "मैं भिखारी नहीं हूँ" कैप्शन ने लोगों का दिल जीत लिया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। कला की कोई सीमा नहीं होती। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस का एक बेहद भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग कलाकार सड़क किनारे बैठकर बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। उनकी मधुर धुन सुनकर राहगीर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कुछ देर के लिए वहीं रुक जाते हैं। इस वीडियो का मुख्य आकर्षण उनके द्वारा रखा गया एक बोर्ड है, जिस पर लिखे शब्दों ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है।

उसके हाथ में जो बोर्ड है, उस पर अंग्रेजी में लिखा हैः मैं भिखारी नहीं हूँ, बस संगीत की मदद से आपकी आत्मा को छूना चाहता हूँ।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति पूरे मन से बांसुरी बजा रहा है। बोर्ड पर लिखे उनके संदेश से स्पष्ट है कि वे लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी अद्भुत कला और संगीत के माध्यम से लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहते हैं। इस उम्र में भी उनका आत्मसम्मान और कला के प्रति प्रेम ही लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णयः वकील की फीस 'अपराध की आय' नहीं है, खाता फ्रीज करना अनुचित है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि आरोपी द्वारा अपने वकील को व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान की गई फीस को "अपराध की आय" नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह भुगतान आरोपी द्वारा किया गया था। जब तक वकील स्वयं आपराधिक कृत्य में शामिल न हो, तब तक उसकी पेशेवर फीस को अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और अरुण कुमार की पीठ उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल द्वारा एक वकील के पूरे बैंक खाते को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, वकील आयुष बाजपेयी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि साइबर सेल ने कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन का हवाला देते हुए उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। खाते में मौजूद धनराशि उनके मुवक्किलों से प्राप्त पेशेवर फीस है। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक वकील सरकार, किसी सम्मानित नागरिक या आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति से भी फीस प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि ऐसा आरोपी वकील के खाते में फीस जमा करता है, तो उस राशि को "अपराध की आय" नहीं कहा जा सकता।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह राशि वकील की वैध पेशेवर आय का हिस्सा है, जो उसे अपने कानूनी कर्तव्यों के निर्वाह के बदले में प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि साइबर सेल केवल संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले लेन-देन के आधार पर किसी पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती।

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल, 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को आएंगे नतीजे, चुनावी सरगर्मियां तेज

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार तीनों राज्यों में 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों के चयन तथा चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी तथा इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

उपचुनाव बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर होंगे। ये तीनों सीटें अलग-अलग कारणों से रिक्त हुई हैं, जिसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयसीमा में उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। इसके बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और पात्रता की समीक्षा होगी। यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद चुनाव मैदान में अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार 30 जुलाई को सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से मतदान करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद सभी मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। इसके बाद 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी और उसी दिन तीनों विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के कारण उन्हें विधानसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीटों में गिना जाता है और यहां होने वाला चुनाव सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हुई। संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया। दतिया क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच लंबे समय से सीधा राजनीतिक मुकाबला रहा है। ऐसे में इस उपचुनाव को दोनों दल आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक योगेशभाई नारायणभाई पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई है। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसे भरने के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन उपचुनाव में विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके लागू होते ही संबंधित क्षेत्रों में सरकार और राजनीतिक दलों के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। अब कोई भी नई सरकारी योजना घोषित नहीं की जा सकेगी और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका हो। सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा तथा अधिकारियों को निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीन का उपयोग अनिवार्य होगा। वीवीपैट प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक मतदाता अपने मतदान की पुष्टि कुछ सेकंड तक मशीन की स्क्रीन पर देख सकेगा, जिससे मतदान प्रक्रिया पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा। आयोग ने सभी मतदान कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने और मशीनों की तकनीकी जांच समय रहते पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों तथा राज्य पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मतदाताओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही यह केवल तीन विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, लेकिन इसके परिणाम संबंधित राज्यों की राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रमुख राजनीतिक दल इन चुनावों को अपनी जनस्वीकृति और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ नेताओं की सभाएं, जनसंपर्क अभियान और राजनीतिक रणनीतियां विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं।

राजस्व पटवारी के रूप में नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले 2300 से अधिक युवाओं को गांधीनगर में नियुक्ति पत्र वितरण का गौरवशाली समारोह संपन्न

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ राजस्व विभाग की अभिनव पहलरूपी विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ तथा नए कार्यालयों का लोकार्पण किया

▸▸ मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पटवारियों का ग्रामीण लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निवारण लाने का सेवा दायित्व निभाने का आह्वान

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ राजस्व पटवारी राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं

▸▸ तकलीफ में हों; ऐसे लोगों के काम आसानी से पूरे करें, जिनका आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद समान है

▸▸ भविष्य में विभाग या सरकार को भी सरलता रहे; ऐसा पद्धतिपूर्ण एवं व्यवस्थतित कामकाज करें

▸▸ लोगों की अपेक्षा संतुष्ट हों; ऐसे कामकाज से घर-परिवार-समाज को प्राउड फील कराएँ

मुख्यमंत्री के करकमलों से नई राजस्व सेवाओं की लॉन्चिंग

▸▸ क्यूआर कोड आधारित रेवेन्यू वॉइस एंड असिस्टेंस :- नागरिक कार्यालयों के साथ रहे अपने अनुभवों तथा कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में फीडबैक क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगे

▸▸ इंटीग्रेटेड रेवन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम में ई-फाइलिंग सुविधा :- आवेदक घर बैठे ही ई-फाइलिंग से रेवेन्यू केस दाखिल कर सकेंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे और केस खत्म होने पर ऑर्डर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजस्व-पटवारी संवर्ग में नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले 2300 से अधिक युवाओं को गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित गौरवशाली समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 21 राजस्व सेवाओं को अधिक सरल एवं तेज बनाने के लिए की गई अभिनव पहलों का शुभारंभ और नए कार्यालयों का लोकार्पण भी किया।

श्री पटेल ने राजस्व-पटवारी को राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी तथा ग्रामीण प्रशासन का आधारस्तंभ बताते हुए नई नियुक्ति प्राप्त कर रहे युवाओं का आह्वान किया कि वे ऐसी जनहितकारी कार्यपद्धति अपनाएँ कि वास्तव में तकलीफ जो व्यक्ति है, उसका काम आसानी से हो जाए। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को होने वाला संतोष और उसका आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद के समान है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "राजस्व पटवारी के रूप में आपका ग्रामीणों की अनेक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निवारण लाने का दायित्व होना चाहिए। इतना ही नहीं; जो कुछ भी काम हो, वह ऐसा व्यवस्थित एवं पद्धतिपूर्ण हो कि राजस्व विभाग में या सरकार में भी उस काम के कारण भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो।"

श्री भूपेंद्र पटेल नो जड़ा कि पटवारी के पास आने वाले लोगों की अपेक्षाएँ यही होती हैं कि उनका काम तेजी व सरलता से हो जाए। इसलिए पटवारी को हमेशा सामने वाले व्यक्ति में अपने आपको दखकर कामकाज का मूल्यांकन करना चाहिए।

उन्होंने नवनियुक्त पटवारियों को उनके घर, परिवार और समाज को गौरव हो; ऐसी कार्यप्रणाली से हमेशा कार्यरत रहने की सीख दी और शुभकामनाएँ दीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत-2047 का जो संकल्प किया है, उसे ये नवनियुक्त युवा विकसित गुजरात के निर्माण से साकार करें।

-: नई राजस्व सेवाओं की लॉन्चिंग :-

नागरिकों के फीडबैक के लिए 'रेवा'

मुख्यमंत्री ने जिन नई राजस्व सेवाओं का लोकार्पण किया, उनमें रेवेन्यू वॉइस एंड असिस्टेंस (रेवा) शामिल है। क्यूआर कोड आधारित इस फीडबैक सिस्टम अंतर्गत राजस्व प्रशासन के कलेक्टर, प्रांत, सब-रजिस्ट्रार, डीएलआईआर तथा तहसीलदार कार्यालय सहित सभी कार्यालयों की सेवाओं के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था कर नागरिकों के फीडबैक प्राप्त करने का यह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम 'रेवा' शुरू किया गया।

इस सिस्टम से कार्यालय में उपलब्ध कराई जाने सावी सुविधाओं तथा कार्यालय के स्टाफ के व्यवहार के बारे में नागरिकों से फीडबैक प्राप्त किए जाएंगे, जो उन्हें दी जाने वाली सेवाओं में अधिक सुधार लाने में उपयोगी बनेंगे।

इंटीग्रेटेड रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम (आईआरसीएमएस) में ई-फाइलिंग की नई सुविधा

पहले आईआरसीएमएस में सभी राजस्व कार्यालयों में मैनुअली रेवेन्यू मामले दर्ज होते थे। उस पद्धति में फेरबदल लाकर अब ई-फाइलिंग से आवेदक घर बैठे ही राजस्व मामले दर्ज करा सकेंगे। परिणामस्वरूप समय व शक्ति का बचाव होगा, आसानी से कम समय में केस दाखिल किया जा सकेगा और आवेदक केस के हर चरण को रीयल टाइम ट्रैक कर सकेगा। केस खत्म होने के बाद आवेदक को आदेश तुरंत ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।

यह पद्धति शुरू होने से समग्र राज्य के सभी कार्यालयों में कामकाज में एकरूपता बनी रहेगी और ई-फाइलिंग की सुविधा से केवल आवेदकों को ही नहीं, बल्कि सभी राजस्व कार्यालयों में चल रहे विभिन्न राजस्व केसों के प्रबंधन में भी सरलता व त्वरितता आएगी।

सिटी सर्वे नक्शों को जियोरेफरेंसिंग करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू

राज्य की सैटलमेंट आयुक्त श्री आर्द्रा अग्रवाल तथा भारत सरकार के एडिशनल सर्वेयर जनरल श्री एम. सी. गोर के बीच सिटी सर्वे नक्शों को जियोरेफरेंसिंग करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया।

राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महीडा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया के फलस्वरूप राजस्व प्रशासन के आधारभूत स्तंभ के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे उम्मीदवारों के जीवन में आज नए अध्याय की शुरुआत हुई है। पूर्व में रिक्त रहे स्थान बड़े पैमाने पर भरे जाने से अब प्रशासनिक क्षमता दुगुनी होगी और गाँवों तक राजस्व सेवाएँ अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से पहुँचेंगी। उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दीर्घदृष्टि के परिणामस्वरूप राजस्व पटवारी का स्वतंत्र संवर्ग अस्तित्व में आया है।

नवनियुक्त कर्मयोगियों को अभिनंदन देते हुए श्री महीडा ने कहा कि राजस्व पटवारी राज्य सरकार का ऐसा आधारभूत अधिकारी है, जिसका प्रथम एवं सबसे निकटतम संपर्क राज्य के आम नागरिक, गरीब और किसान के साथ होता है। गाँव का आम आदमी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए सबसे पहले पपटवारी के पास ही आता है। इसलिए कर्मचारियों के व्यवहार-आचरण, निर्णय, भाषा तथा कार्यशैली से ही नागरिक समग्र सरकार की कार्यपद्धति एवं नीयत का अनुभव करते हैं। उनके साथ सद्व्यवहार किया जाएगा, तो शासन व्यवस्था पर नागरिकों का विश्वास और सुदृढ़ बनेगा।

उन्होंने कहा कि पटवारी जिस कागज पर हस्ताक्षर करता है, वह केवल आम दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकार, किसान के विश्वास और राज्य के विकास की प्रक्रियाओं का मूलभूत आधार है। कर्मचारियों की छोटी भूल गरीब को मुश्किल में डाल सकती है और एक सकारात्मक निर्णय किसी के जीवन में आशा का दीप प्रज्ज्वलित कर सकती है।

मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने नवनियुक्त राजस्व पटवारियों को अभिनंदन देते हुए कहा, "आप सबका चयन किसी सिफारिश या प्रभाव या दबाव के बल पर नहीं, अपितु केवल और केवल आपकी क्षमता, कड़े परिश्रम एवं मैरिट के आधार पर हुआ है, जो आप सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है।" उन्होंने जोड़ा कि ग्रामीण स्तर पर आज भी पटवारी का पद बहुत ही आदरणीय एवं दायित्वपूर्ण माना जाता है। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन भूमि का प्रबंधन तथा राजस्व प्रशासन सदैव शासन एवं प्रशासन के केन्द्र में रहा है। इसलिए नवनियुक्त पटवारियों को यह दायित्व निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने भूमि प्रशासन का महत्व समझाते हुए कहा, "किसी भी प्रकार के विकास कार्य जमीन के बिना संभव नहीं है। इसलिए गाँव के लैंड रिकॉर्ड को 100 प्रतिशत सटीक एवं क्षतिरहित रखने और सरकारी जमीनों, गौचर या तालाबों पर होने वाले अवैध अतिक्रमणों को रोककर उन पर कड़ी निगरानी रखने की जिम्मेदारी आप नवनियुक्त पटवारियों की रहेगी।"

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने स्वागत संबोधन में कहा, "राजस्व विभागांतर्गत 2389 राजस्व पटवारियों के रिक्त पद भरने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। गाँव के नागरिकों को अधिक अच्छी सेवाएँ उपलब्ध हों; इसके लिए मुख्यमंत्री ने पटवारी का जॉब चार्ट भी निर्धारित कराया है। गाँव में पटवारी सरकार का चेहरा है। पटवारी को गाँव में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों, चुनाव, गणना जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ और कामकाज करने होते हैं। ऐसे में अपेक्षा है कि आप सभी नवनियुक्त कर्मयोगी निष्ठा एवं प्राणामिकता से कार्य करेंगे।"

उन्होंने राजस्व पटवारी की पारदर्शी एवं तेज भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सम्बद्ध सभी विभागों को अभिनंदन दिया।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्री मीराबेन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेशभाई पटेल, गांधीनगर उत्तर की विधायक श्री रीटाबेन पटेल, सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, गुजरात गौण सेवा चयन मंडल के अध्यक्ष श्री तुषार धोळकिया, राजस्व जाँच आयुक्त श्री राजेश मांजू, राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी सहित नियुक्ति प्राप्त करने वाले राजस्व पटवारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में सभी जिलों से पदाधिकारी, कलेक्टर सहित नवनियुक्त राजस्व पटवारी वर्चुअल माध्यम से सहभागी हुए।

राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव श्री सचिन पटवर्धन ने आभार ज्ञापन किया।

अहमदाबाद में 'फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालीफायर्स विंडो 3' का शानदार शुभारंभ

▸▸ वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 जुलाई को भारत का मुकाबला कतर से तथा 5 जुलाई को लेबनान से होगा

▸▸ विभिन्न प्रतिष्ठित खेलों के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के साथ अहमदाबाद लगातार एक बड़े 'स्पोर्ट्स हब' के रूप में उभर रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर : अहमदाबाद 'फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालीफायर्स – विंडो 3' की मेजबानी कर रहा है। इसमें भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम 2 जुलाई से 5 जुलाई, 2026 के दौरान नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशिया की दो मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीमों के विरुद्ध टकराएगी।

भारत ने 2 जुलाई गुरुवार को कतर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तथा इसके बाद वह 5 जुलाई को लेबनान से भिड़ेगा। क्वालीफिकेशन के लिए ये दोनों मैच अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि विभिन्न खेलों के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के साथ अहमदाबाद लगातार एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि इसी स्थल पर 'एवीसी मेन्स वॉलीबॉल कप' का सफल आयोजन किए जाने के कुछ ही दिनों बाद शहर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट - 'फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालीफायर्स (विंडो 3)' का स्वागत कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 का एवीसी मेन्स वॉलीबॉल कप 20 से 28 जून, 2026 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, जो भारत में इस टूर्नामेंट का पहला आयोजन था।

श्री हर्ष संघवी ने आगे कहा, "अहमदाबाद तेजी से एक प्रीमियर स्पोर्ट्स हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मात्र एक सप्ताह के भीतर एक और बड़े अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करना गुजरात के वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को प्रोत्साहन देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

ये मैच फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के एशियन क्वालीफायर्स में भारत के अभियान का एक हिस्सा हैं। हेड कोच स्कॉट फ्लेमिंग के मार्गदर्शन में भारतीय टीम वर्तमान में युवा प्रतिभाओं को निखारने तथा मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने पर विशेष जोर देकर पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है।

नवीनतम फिबा रैंकिंग में विश्व में 76वें तथा एशिया में 14वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम क्वालीफिकेशन अभियान की चुनौतीपूर्ण शुरुआत के बाद अब बेहतर प्रदर्शन की आशा करेगी। अहमदाबाद के होम ग्राउंड (स्थानीय दर्शकों के समर्थन) का लाभ टीम को अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध मजबूत चुनौती पेश करने के लिए बड़ा आत्मविश्वास प्रदान करेगा।

भारतीय टीम में कँवर संधु, प्रणव प्रिंस, प्रिंसपाल सिंह तथा हर्ष डागर जैसे कुछ आशावान खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने हाल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

अहमदाबाद चार दिनों तक अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल मैचों का साक्षी बनने जा रहा है। ऐसे में अपेक्षा है कि बड़ी संख्या में बास्केटबॉल प्रेमी राष्ट्रीय टीम का समर्थन करने पहुंचेंगे। एशियाई बास्केटबॉल में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये दोनों मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

राजकोट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर करोड़ों के खर्च का विवाद, चाय-नाश्ते से लेकर पानी तक के बिलों ने खड़े किए सवाल, भुगतान पर रोक

राजकोट। गुजरात के राजकोट नगर निगम (आरएमसी) द्वारा जंगलेश्वर क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अभियान समाप्त होने के बाद नगर निगम के समक्ष तीन करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें चाय, नाश्ता, मिठाइयां, भोजन, बोतलबंद पानी, टेंट, वीडियोग्राफी और ड्रोन निगरानी जैसे मदों में असामान्य रूप से अधिक खर्च दर्शाया गया है। बिलों की राशि सामने आने के बाद नगर निगम के नवगठित राजनीतिक बोर्ड ने भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है और पूरे मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया है। अब यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नगर निगम की खरीद प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, जंगलेश्वर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी संख्या में निगम कर्मचारी, पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात किए गए थे। अभियान के बाद विभिन्न विभागों की ओर से जो बिल प्रस्तुत किए गए, उनमें कई मदों में खर्च सामान्य सरकारी मानकों की तुलना में काफी अधिक पाया गया। इसी कारण स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे भुगतान की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

सबसे अधिक चर्चा चाय-नाश्ते और भोजन पर किए गए खर्च को लेकर हो रही है। नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार केवल रिफ्रेशमेंट के नाम पर लगभग 27.20 लाख रुपये का बिल पेश किया गया है। इस बिल में 21,310 कप चाय, 13,390 विशेष लंच प्लेट, काजू कतली, जलेबी, खजूर रोल तथा अन्य खाद्य सामग्री का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि यह भोजन और नाश्ता अभियान में तैनात कर्मचारियों के साथ-साथ मौके पर मौजूद लगभग 190 मीडिया प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया गया था। हालांकि इतनी बड़ी राशि और खाद्य सामग्री की मात्रा को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

पीने के पानी पर हुए खर्च ने भी जांच एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है। रिकॉर्ड के अनुसार अभियान के दौरान लगभग 4,800 कर्मचारियों के लिए बोतलबंद मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए करीब 12.40 लाख रुपये का बिल प्रस्तुत किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 200 मिलीलीटर की पानी की प्रत्येक बोतल के लिए नगर निगम से 8 रुपये की दर वसूली गई। जबकि अधिकारियों का कहना है कि इसी प्रकार की बोतल थोक बाजार में तीन रुपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध होती है और सामान्य खुदरा बाजार में इसकी कीमत लगभग पांच रुपये होती है। इस मूल्य अंतर ने खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अभियान के दौरान लगाए गए अस्थायी टेंट और शेल्टर के लिए भी लगभग 9.94 लाख रुपये का दावा किया गया है। इसके अलावा पूरे अभियान की वीडियोग्राफी, ड्रोन सर्विलांस और कैमरा सेवाओं पर लगभग 22 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया है। नगर निगम अब यह जांच कर रहा है कि इन सेवाओं के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं तथा प्रस्तुत किए गए बिल वास्तविक कार्य के अनुरूप हैं या नहीं।

जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि विभिन्न मदों के भुगतान अलग-अलग विभागों के माध्यम से किए जाने की तैयारी की गई थी। अधिकारियों के अनुसार भोजन और रिफ्रेशमेंट से संबंधित खर्च का भुगतान फ्लावर एंड गार्डन विभाग के माध्यम से किया जाना था, जबकि पेयजल, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े बिलों का भुगतान कल्चरल विभाग के जिम्मे रखा गया था। स्टैंडिंग कमेटी अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस प्रकार विभागों के माध्यम से भुगतान कराने का कोई वैध प्रशासनिक आधार था अथवा वित्तीय प्रक्रियाओं से बचने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।

नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सभी लंबित भुगतानों पर तत्काल रोक लगा दी है। समिति का कहना है कि जब तक प्रत्येक बिल की विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती और खर्च की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक किसी भी एजेंसी या ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसी उद्देश्य से विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि वह खरीद प्रक्रिया, निविदा प्रणाली, बिल तैयार करने की प्रक्रिया, भुगतान स्वीकृति और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच करे। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कहीं खरीद, बिलिंग, मूल्य निर्धारण या भुगतान की मंजूरी में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी, नियमों की अनदेखी या जानबूझकर अनियमितता तो नहीं बरती गई।

नगर निगम के सूत्रों का कहना है कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

सूरत नगर निगम का बड़ा फैसला, सड़क टूटने या धंसने पर अब ठेकेदार ही देगा मरम्मत का खर्च, गुणवत्ता से समझौते पर सख्ती

सूरत। मानसून के दौरान बार-बार धंसती सड़कों, निर्माण कार्यों के बाद बनने वाले गड्ढों और नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) ने निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त ने सभी विभागों और जोन कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब निगम के सभी नए टेंडरों में ऐसी अनिवार्य शर्त जोड़ी जाएगी, जिसके तहत निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यदि सड़क टूटती है, धंसती है या उसमें गड्ढे बनते हैं, तो उसकी मरम्मत और रखरखाव का पूरा खर्च संबंधित ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा। इस निर्णय को नगर निगम द्वारा निर्माण गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार हर वर्ष मानसून के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज तथा अन्य भूमिगत परियोजनाओं के लिए खुदाई की जाती है। कार्य पूरा होने के बाद कई स्थानों पर सड़कें कुछ ही समय में धंसने लगती हैं या बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार नगर निगम को दोबारा सार्वजनिक धन खर्च कर इन सड़कों की मरम्मत करानी पड़ती है, जिससे वित्तीय बोझ भी बढ़ता है।

इन्हीं लगातार सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए नगर आयुक्त ने एक तत्काल (अर्जेंट) परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सीवरेज, स्टॉर्म ड्रेनेज तथा अन्य संबंधित परियोजनाओं के सभी नए टेंडरों में ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली विशेष शर्त अनिवार्य रूप से शामिल की जाएगी। इसके तहत यदि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किसी भी कारण से सड़क की सतह क्षतिग्रस्त होती है, सड़क धंसती है या गड्ढे बनते हैं, तो संबंधित ठेकेदार को अपने खर्च पर तत्काल उसकी मरम्मत करनी होगी। इसके साथ ही आवश्यक रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी एजेंसी की होगी जिसने संबंधित कार्य किया है।

नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से ठेकेदार निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता के प्रति अधिक गंभीर होंगे। अब उन्हें यह पता होगा कि यदि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया तो भविष्य में मरम्मत का पूरा आर्थिक भार उन्हें स्वयं उठाना पड़ेगा। इससे निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों का बेहतर पालन होने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर निगम ने यह भी स्वीकार किया है कि बार-बार सड़क धंसने की घटनाओं से नागरिकों में असंतोष बढ़ा है और इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। बारिश के मौसम में गड्ढों और धंसी हुई सड़कों के कारण वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी घटनाओं को कम करना और नागरिकों को सुरक्षित एवं बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में स्थायी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने फरवरी 2026 में नगर आयुक्त को भेजे गए एक विस्तृत नोट में इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि विभिन्न विभागों द्वारा भूमिगत कार्य पूरे होने के कुछ ही समय बाद सड़कें धंसने लगती हैं, जिससे नगर निगम की छवि प्रभावित होती है और जनता में प्रशासन के प्रति असंतोष बढ़ता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि टेंडर की शर्तों में संशोधन कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी सीधे संबंधित ठेकेदारों पर तय की जाए।

स्थायी समिति के सुझाव पर विचार करने के बाद नगर आयुक्त ने सभी जोन कार्यालयों, अभियंता शाखाओं तथा संबंधित विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में जारी होने वाले प्रत्येक टेंडर के 'स्कोप ऑफ वर्क' में यह शर्त स्पष्ट रूप से शामिल रहे, ताकि किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक अस्पष्टता न रहे।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नई नीति केवल दंडात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि निर्माण गुणवत्ता सुधारने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इससे ठेकेदार बेहतर तकनीक, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री और वैज्ञानिक कार्यप्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही निगम को बार-बार मरम्मत पर अतिरिक्त सार्वजनिक धन खर्च करने की आवश्यकता भी कम होगी।

शहर के नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नगर निगम के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यदि निर्माण कार्य की जवाबदेही सीधे ठेकेदारों पर तय की जाती है और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है, तो सड़क धंसने और गड्ढों की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि जवाबदेही तय होने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा, सार्वजनिक संसाधनों की बचत होगी और शहर की आधारभूत संरचना अधिक टिकाऊ एवं सुरक्षित बन सकेगी।

लखनऊ से संचालित अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का भंडाफोड़, पांच राज्यों में फैले नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 119 गिरफ्तार, 250 करोड़ की ठगी की आशंका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने विभूतिखंड क्षेत्र स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत में चल रहे कथित फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इस गिरोह द्वारा 250 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी किए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका नेटवर्क देश के कम से कम पांच राज्यों में फैला हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी का पूरा तंत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा था और इसका मुख्य निशाना विदेशी नागरिक, विशेष रूप से अमेरिका के निवासी थे। आरोपी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बैंकिंग संस्थानों और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें विभिन्न प्रकार की झूठी कहानियां सुनाकर आर्थिक जाल में फंसा लेते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 103 लैपटॉप, 177 मोबाइल फोन, इंटरनेट कॉलिंग से जुड़े उपकरण, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन उपकरणों से पूरे गिरोह के संचालन, विदेशी संपर्कों, बैंकिंग लेन-देन, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन और हवाला नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। बरामद डिजिटल सामग्री की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरोह विदेशी नागरिकों को फोन कर स्वयं को प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि, तकनीकी सहायता विशेषज्ञ, बैंक अधिकारी अथवा सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताता था। इसके बाद उन्हें बैंक खाते में संदिग्ध लेन-देन, कंप्यूटर में वायरस, तकनीकी खराबी, टैक्स संबंधी समस्या या अश्लील सामग्री से जुड़े कथित मामलों का भय दिखाया जाता था। कई मामलों में पीड़ितों को यह कहकर डराया जाता था कि यदि उन्होंने तत्काल निर्देशों का पालन नहीं किया तो उनके बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है अथवा उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह विशेष रूप से बुजुर्ग अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था। आरोपियों को पता था कि वरिष्ठ नागरिक तकनीकी मामलों की जानकारी कम होने के कारण आसानी से झांसे में आ सकते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्हें मानसिक दबाव में लाकर गिफ्ट कार्ड खरीदने, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भुगतान करने अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों से धन भेजने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार किए गए भुगतान सामान्य बैंकिंग निगरानी से काफी हद तक बाहर रहते थे, जिससे अपराधियों के लिए धन का पता लगाना कठिन हो जाता था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी से प्राप्त धन सीधे भारत नहीं लाया जाता था। इसके लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके माध्यम से विदेशों से अवैध रूप से धन भारत पहुंचाया जाता था। जांच एजेंसियां अब हवाला कारोबार से जुड़े लोगों, बैंक खातों, क्रिप्टो वॉलेट और अन्य वित्तीय माध्यमों की भी जांच कर रही हैं, ताकि पूरे आर्थिक नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार यह फर्जी कॉल सेंटर कथित तौर पर 'सोलारिस सॉल्यूशन' के नाम से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम सिंह परमार सहित कई प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान कॉल सेंटर के कथित मुख्य संचालक विनीत शर्मा और उसके अन्य सहयोगियों की भूमिका भी सामने आई है।